

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00446 (326/2018) 223 आरटीएक्ट

रमेश कुमार पुत्र दलवीरसिंह आदि जाति चमार निवासी दडबाकला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा हाल आबाद भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

— अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहनी देवी उर्फ गिरदावरी पत्नी बनवारी पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुड्डी पत्नी हरीसिंह पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मराम पुत्र सुरजाराम जाति धानक निवासी कलाना तहसील भादरा
4. कमला पत्नी गोपीराम पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा (मृतक)
4/1 गोपीराम
4/2 विनोद } पि० गोपीराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा
4/3 सुरेन्द्र }
4/4 सुमन } पि० गोपीराम नाबालिग जरिये कुदरति वली पिता गोपीराम जाति
4/5 कृष्णा } धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा — रेस्पोजेण्ट

विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2010 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा प्रकरण संख्या 319/2002 (180/02)

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनीराम सरावग एवं लौकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं० 1, 2,

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक:- 13.06.2019

1. सहायक कलक्टर भादरा के समक्ष रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2/वादीगण ने दावा इशतकाररहक व खाता तकसीम प्रस्तुत कर रोही मौजा कलाना तहसील भादरा के हाल खसरा नं. 637 की 33 बीघा 15 बिस्वा में वादी संख्या 1 का 1/4 भाग, वादी 2 का 1/4 भाग, प्रतिवादी 1 का 1/4 भाग, प्रतिवादी 2 का 1/4 भाग होने की उद्घोषणा एवं जमाबंदी हाल खाता इतकाल वादीगण के हकों के मुकाबले शून्य व बेअसर होने एवं बाद करने उद्घोषणा अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दावा



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्राथमिक डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 18.06.1993 से रेस्पोजेण्ट संख्या 3 से खसरा नं. 637 की 33 बीघा 15 बिस्वा पश्चिमि तरफ की भूमि खरीद की हुई है। खरीद के रोज से अपीलान्ट काबिज था एवं अपीलान्ट ने यह भूमि शिला पत्नी औमप्रकाश को एवं शिला ने रोशनी पत्नी सुभाष चन्द को विक्रय कर दी है। ये बैयनामे प्रभाव में रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 18.06.1993 के विक्रय पत्र को गलत रूप से निष्प्रभावी घोषित किया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होने से वाद पोषणीय नहीं था। जब रेस्पोजेण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा ही नहीं था तो वह उदघोषणा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकती थी और रजिस्टर्ड बैयनामे को राजस्व न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता है। बैयनामे के निष्पादन से किसी पक्षकार ने इन्कार नहीं किया है। दौराने वाद भूमि का विक्रय अवैध नहीं है बल्कि धारा 52 हस्तान्तरण अधिनियम के तहत हस्तान्तरित डिक्री से बाध्य है। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अब न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपील स्वीकार करने एवं बैयनामा दिनांक 18.06.1993 के पूर्णतः विधि सम्मत होने में अपनी सहमति भी जाहिर की है एवं अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2019 व आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2019 के अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं बहस में आये तथ्यों के आधार पर एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलान्ट का धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
7. उपखण्डाधिकारी भादरा द्वारा अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा को डिक्री करते हुए प्रश्नगत भूमि को सुरजाराम की खातेदारी होना मानते हुए सुरजाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार कर वाद डिक्री किया है एवं दौराने वाद भूमि में हिस्से से अधिक विक्रय की गई भूमि को वादीगण के अधिकारों पर पाबंदी आयद होना नहीं मानते हुए एवं इस प्रकार के बयनामे को प्रारम्भ से ही शून्य होना मानते हुए वाद डिक्री किया है। अपीलान्ट ने अपील में यह तर्क दिया है कि बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2 वादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर बैयनामा दिनांक 18.06.1993 को विधि



सम्मत होने का कथन करते हुए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 13.10.2010 को निरस्त करने में अपनी सहमति दी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो रिपोर्ट हल्का पटवारी है जिसके साथ प्रस्तुत जमाबंदी के कॉलम नं. 4 में धर्मा वल्द सुरजा 275 हिस्सा, शिला पत्नी औरमप्रकाश 400 हिस्सा खातेदार रहिन धर्मा हिस्सा एमजीबी कलाना एवं कॉलम नं. 12 में शिला हिस्सा रहिन आईसीआईसीआई शाखा सिकरोडी के नाम भी रहन दर्ज है। परन्तु दावा में सम्बन्धित बैंक एवं शिला को पक्षकार नहीं बनाया जाना पाया जाता है जो कि दावा में आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलाण्ट रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान एवं बैंक को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

8. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भांदरा का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान एवं बैंक को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)
 (मूल चन्द आरएस)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़